

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1981
जिसका उत्तर बुधवार, 03 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

न्याय क्लॉक सिस्टम

+1981. श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के जिला न्यायालयों के कार्यकरण की गति की निगरानी करने के लिए जस्टिस क्लॉक सिस्टम स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है/तैयार की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में न्याय क्लॉक की स्थापना करना अपने अपने उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

इस संबंध में उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के संसाधनों के वर्धन के लिए , केन्द्रीय सरकार ने वर्ष (2020-2025) के दौरान 3,350 न्यायालय परिसरों में न्याय क्लॉक की स्थापना के लिए , पंद्रहवें वित्त आयोग को 435.50 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।
